पाकिस्तान पर हमले का इंतजार कर रहा पूरा देश

उत्तराखंड का भू-कानून 2025 लागू, आंशिक विजय

प्रकाशन का गौरवाशाली 14वाँ वर्ष

दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका

नज़र सब पर

वर्ष 14 | अंक 50 | मूल्य 15 रुपये | 04-10 मई, 2025

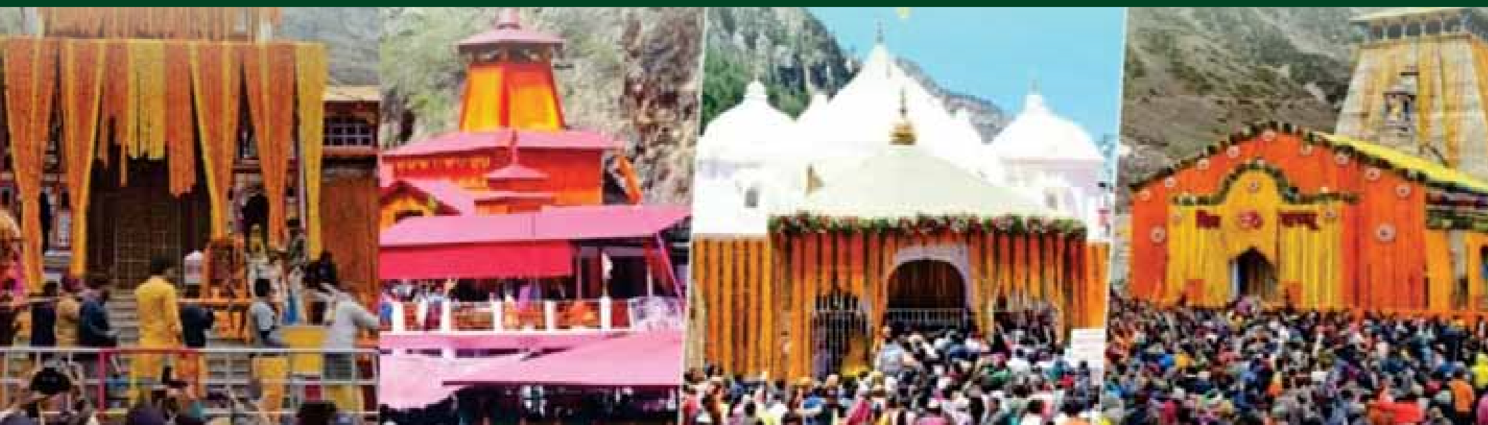

चारों धामों के खुले कपाट

सीएम धामी के प्रबंध और सेवा भाव से अभिभूत तीर्थयात्री

EXPERIENCE HELI TOUR WITH

Himgiri Aviation & Tourism

3N/4D TOUR

Do Dham

YATRA BY HELICOPTOR

LIMITED SEATS ARE LEFT **BOOK NOW**

Contact for Reservation **8433456398, 9410353164**

Email: himgiritourism@gmail.com

6 Municipal Road, Opps. Bala hissar Academy, Dalanwala, Dehradun-248001 (UK)

वर्ष 14 | अंक 50

दिव्य हिमगिरि

04-10 मई, 2025

संपादक
कुँवर राज अस्थाना

वरिष्ठ संवाददाता
शंभूनाथ गौतम

ब्यूरो प्रमुख
मोनिका डबराल

विज्ञापन
पूनम आर्या

ग्राफिक डिजायनर
देव भट्ट

संवाददाता
हरिद्वार : डॉ. रजनीश गौतम
पौडी : रत्नमणि भट्ट
कोटद्वार : के.पी. बौंठियाल
रूद्रपुर : हेमचन्द्र बुडलाकोटी
चमोली : मुकेश रावत
रुड़की : श्रीगोपाल नारसन
नैनीताल : शीतल तिवारी
अल्मोड़ा : संजय कुमार अग्रवाल (एड.)
विकासनगर : अजय शर्मा
प्रसार : रमेश सिंह रावत

संपादकीय कार्यालय : 6, म्युनिसिपल रोड, बाला हिसार स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून (उत्तराखंड)
मोबाइल : +91 8433456398, 9410353164
Email: divyahimgiriddn@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक कुँवर बहादुर अस्थाना द्वारा सरस्वती प्रेस, 2, ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, देहरादून से मुद्रित तथा 39/7 ई, ई. सी. रोड, (निकट मार्शल स्कूल सीनियर विंग) देहरादून-248001 उत्तराखण्ड से प्रकाशित।
संपादक: कुँवर बहादुर अस्थाना*

*(पीआरबी एक्ट के तहत प्रकाशित सामग्री के लिए उत्तरदायी)

ईडी को सरकार की नसीहत

अतिरिक्त महाधिवक्ता के ताजा बयान से उम्मीद बनी है कि ईडी अपनी कार्रवाइयों में कुछ सतर्कता और कानूनी मूल्यों का ध्यान रखेगी, न कि केवल अपने अधिकारों का मनमानी उपयोग करेगी। मगर इसके साथ ही, यह भी देखने की बात होगी कि ईडी अपने को सरकारी दबाव से किस हद तक मुक्त कर पाती है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाइयों को लेकर लंबे समय से अंगुलियां उठती रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय भी कुछ मौकों पर उसके अधिकारियों को फटकार लगा चुका है कि वे धनशोधन के मामलों में गिरफ्तारियां तो खूब करते हैं, पर उनमें दोषसिद्धि की दर बहुत कम है। इससे उनकी कार्रवाई पर संदेह होता है। हालांकि अतिरिक्त महाधिवक्ता एसवी राजू ने अनेक मौकों पर अदालतों में ईडी का बचाव किया है, मगर उन्होंने भी खुद प्रवर्तन निदेशालय के स्थापना दिवस के मौके पर उसके अधिकारियों को नसीहत दी कि धनशोधन के मामलों में गिरफ्तारियों में संयम बरतें। शुरुआती चरण में ही गिरफ्तारी न करें। गंभीरता से जांच करने के बाद ही गिरफ्तारी का विचार करें और उसका आधार प्रस्तुत करें, नहीं तो अदालतों में उन्हें बेहतर नतीजे नहीं मिल पाएंगे। अतिरिक्त महाधिवक्ता की इस नसीहत की वजह समझी जा सकती है। पिछले कुछ वर्षों में ईडी ने धनशोधन से जुड़े मामलों में बहुत तेजी से कार्रवाइयां की हैं। थोड़े-थोड़े अंतराल पर उसकी छापेमारी चलती रहती है। यही वजह है कि करीब नौ वर्षों में उसने सवा पांच हजार से अधिक मामले दर्ज कर लिए। उनमें से ज्यादातर मामलों में गिरफ्तारियां भी हुईं। मगर दोषसिद्धि केवल चालीस मामलों में हो पाई है। यह भी छिपी बात नहीं है कि जांच एजेंसियों की कार्रवाइयों के पीछे केंद्र सरकार का दबाव रहा है, जिसके चलते ज्यादातर छापेमारियां और गिरफ्तारियां विपक्षी दलों से जुड़े लोगों के खिलाफ हुई हैं। इसलिए इन कार्रवाइयों को लेकर सत्तापक्ष लगातार विपक्ष के निशाने पर रहा है। मगर अतिरिक्त महाधिवक्ता की चिंता यह है कि उन मामलों में अदालत के सामने उन्हें ही दलील पेश करनी पड़ती है और अक्सर मामले कमजोर होने पर उन्हें अदालत की फटकार भी सुननी पड़ी है। इसलिए उन्होंने ईडी अधिकारियों को सीख दी है कि वे केवल मौखिक बयानों के आधार पर गिरफ्तारी का आधार न बनाएं। यही बात सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष एक मामले की सुनवाई के वक्त कही थी। मगर उस पर ईडी की दलील थी कि धनशोधन निवारण कानून की धारा पचास के तहत उसे मौखिक बयानों के आधार पर गिरफ्तारी का अधिकार प्राप्त है। मगर अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत से बाहर उसी दलील के उलट पाठ पढ़ाया है कि कई बार लोग गिरफ्तारी के डर से कुछ बातें कबूल कर लेते हैं, पर बाद में अदालत के सामने अपने बयान से मुकर जाते हैं। इसलिए मौखिक बयानों को आधार न बनाएं। दरअसल, भ्रष्टाचार रोकने के मकसद से धनशोधन निवारण कानून में बदलाव कर प्रवर्तन निदेशालय को काफी हद तक मुक्तहस्त बना दिया गया है। गिरफ्तारियों से संबंधित कानूनों को काफी लचीला बना दिया गया है। कई मामलों में ईडी को गिरफ्तारी के लिए इजाजत लेने या इत्तिला करने की जरूरत नहीं रह गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन माना था, मगर ईडी ने मौलिक अधिकारों के ऊपर अपने अधिकारों को ज्यादा तरजीह दी है। अतिरिक्त महाधिवक्ता के ताजा बयान से उम्मीद बनी है कि ईडी अपनी कार्रवाइयों में कुछ सतर्कता और कानूनी मूल्यों का ध्यान रखेगी, न कि केवल अपने अधिकारों का मनमानी उपयोग करेगी। मगर इसके साथ ही, यह भी देखने की बात होगी कि ईडी अपने को सरकारी दबाव से किस हद तक मुक्त कर पाती है।

कुँवर राज अस्थाना

चारों धामों के खुले कपाट

सीएम धामी के प्रबंध और सेवा भाव से अभिभूत तीर्थयात्री

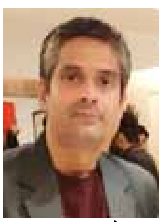

शंभू नाथ गौतम
वरिष्ठ पत्रकार

उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू होने से रौनक दिखाई दे रही है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड में विधिवत रूप से चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। गंगोत्री और केदारनाथ धाम खुलने के दौरान सीएम धामी स्वयं पहुंचे और श्रद्धालुओं के पर पुष्प वर्षा की। धाम में सीएम को अपने पास पाकर हजारों श्रद्धालु का उत्साह और बढ़ गया। मुख्यमंत्री ने कहा इस वर्ष भी चारधाम यात्रा नया कीर्तिमान बनाएगी। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने चार धाम यात्रा के सुव्यस्थित और सफल संचालन के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा सुरक्षा और सुगमता के लिए सरकार ने सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। उन्होंने कहा हम सभी उत्तराखंडवासियों का कर्तव्य है कि हम देश और दुनिया से आने वाले अतिथियों का स्वागत आत्मीयता और सेवा भाव से करें। चारों धामों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 23 लाख से ज्यादा पहुंच गया है। अब तक कुल 57,284 श्रद्धालु ऑफलाइन पंजीकरण करा चुके हैं।

उत्तराखंड में सबसे बड़े धार्मिक उत्सव चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए। उसके बाद 2 मई को बाबा केदारनाथ धाम और 4 मई, रविवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड में विधिवत रूप से चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। चारधाम यात्रा का आगाज होते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। हर साल चार धाम यात्रा शुरू होने से पूरे प्रदेश भर में अलग नजारा दिखाई देता है। देश-विदेश से लाखों तीर्थ यात्री चार धाम में दर्शन करने पहुंचते हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक अलग रौनक दिखाई देती है। इस बार भी चार धाम यात्रा शुरू होने से उत्तराखंड में रौनक शुरू हो गई है। इस बार यह यात्रा नया कीर्तिमान बनाने जा रही है। यात्रा से दुकानदारों, होटल संचालकों, बस-टैक्सी आदि व्यवसाय से हजारों लोगों की रोजी-रोटी भी जुड़ी हुई है। इसके साथ चार धाम यात्रा से आने वाला राजस्व भी प्रदेश सरकार को 'मालामाल' करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा की कमान पूरी तरह से संभाल रखी है। कुछ समय पहले ही प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 50 करोड़ से अधिक की भीड़ को जिस प्रकार से मैनेजमेंट किया है उसकी प्रशंसा देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में की गई। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी भी चाहेंगे इस बार चार धाम यात्रा के दौरान सुरक्षा से लेकर व्यवस्था की कोई कमी न रहे। हालांकि यह भी सही है कि प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ और चार धाम यात्रा में अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो काफी अंतर भी है। प्रयागराज मैदानी क्षेत्र में आता है वहीं यहां पर पहाड़ी और दुर्गम रास्ते भी यात्रियों के लिए कम जोखिम भर रहते हैं। इसके साथ सबसे बड़ी समस्या हर साल मौसम की भी रहती है। पहाड़ों पर अचानक मौसम खराब होने की वजह से यात्रा मार्गों पर व्यवधान आता है और श्रद्धालु फंसे रहते हैं। इन सभी समस्याओं को देखते हुए सीएम धामी ने इस बार सुरक्षा के साथ व्यवस्था भी अपने हाथ में ले ली है। इसी साल जनवरी महीने में आयोजित राष्ट्रीय खेलों का मुख्यमंत्री ने कुशल मैनेजमेंट दिखाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी खूब प्रशंसा भी की। इसके साथ प्रदेश के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ भी यात्रा को लेकर एक्टिव हैं। प्रदेश के डीजीपी रहते हुए दीपम सेठ की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि इस बार चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षा संबंधी कोई परेशानी न हो। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ यात्रा में पूरी नजर रखे हुए हैं। पिछले महीने में 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद श्रद्धालुओं की

ऋषिकेश से सीएम धामी ने चार धाम यात्रा का किया शुभारंभ, श्रद्धालुओं से की बात

चारधाम यात्रा का शनिवार को विधिवत शुभारंभ हो गया। ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप परिसर में चार धाम यात्रा संचालित करने वाली संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति ने चार धाम यात्रा के शुभारंभ पर कार्यक्रम का आयोजन किया। जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे। मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा पर जा रही 10 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं से बातचीत की। उनसे ट्रांसिट कैंप परिसर में व्यवस्थाओं के बारे में भी पूछा। मुख्यमंत्री से मिलकर श्रद्धालु काफी खुश और गदगद नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा इस बार की यात्रा ऐतिहासिक होने जा रही है। सरकार ने पिछले वर्ष की यात्रा से सीख लेकर कई नई व्यवस्थाएं की हैं। जिसमें सबसे पहले ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था को सुधारा गया है। इसके अलावा चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं।

सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 30 अप्रैल को गंगोत्री धाम के कपाट खुलने पर मुख्यमंत्री धामी मौजूद रहे। इस दौरान हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की गई। ऐसे ही केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले ही सीएम धामी पहुंचे। यहां भी हजारों श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। यही नहीं पहले दिन लाइन में लगे श्रद्धालुओं से मुख्यमंत्री ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फीडबैक भी लिया। केदारनाथ धाम में सीएम को अपने पास पाकर हजारों श्रद्धालु का उत्साह और बढ़ गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद नियमित तौर पर चार धाम की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सीएम धामी ने बीते दिनों देहरादून में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया था। उन्होंने बताया था, हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को बिना किसी परेशानी के चार धाम के दर्शन कराए जाएं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा चारधाम यात्रा उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सीएम धामी ने कहा था कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस यात्रा को और सरल बनाने के लिए अगर कोई अतिरिक्त कार्य करने की आवश्यकता होगी, तो उसे तत्काल पूरा किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की कमी न रहे और श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव प्रदान किया जाए।

केदारनाथ में मुख्य सेवक भंडारा में सीएम ने श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया

केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर केदारनाथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ परिसर में आयोजित मुख्य सेवक भंडारा में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ की स्वच्छता में लगे पर्यावरण मित्रों, पुनर्निर्माण कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सपत्नीक मुख्य सेवक भंडारा के तहत श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया और भोजन परोसा। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने मुख्य सेवक भंडारा का प्रसाद ग्रहण किया। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ आए श्रद्धालुओं से मुलाकात की एवं उनसे यात्रा को लेकर की गई व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। यात्रा के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत एवं उनकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत वर्ष केदारनाथ क्षेत्र में आपदा आई थी, जिससे करीब 35 दिन यात्रा बाधित रही। सरकार और प्रशासन ने स्थानीय लोगों के सहयोग से यात्रा को पुन: शुरु किया, जिससे फलस्वरूप रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु चारधाम आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर स्तर पर यात्रा की लगातार मॉनिटरिंग करती है। यात्रा मार्गों में भी विभिन्न मूलभूत सुविधाएं स्थापित की गई हैं। उन्होंने कहा चारधाम यात्रा राज्य की लाइफलाइन भी है। यह यात्रा लाखों लोगों की आजीविका का साधन भी है। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार का संकल्प है कि चारधाम यात्रा साल भर चले, जिसके लिए राज्य में शीतकालीन यात्रा को भी प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए मुखवा, उत्तरकाशी में मां गंगा के दर्शन किए थे। मुख्यमंत्री ने समस्त प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री का आभार किया। उन्होंने कहा केदारनाथ का पुनर्निर्माण कार्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। प्रधानमंत्री केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य की नियमित समीक्षा करते हैं। 2000 करोड़ की लागत से केदारनाथ का भव्य निर्माण कार्य जारी है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने गौरीकुंड से केदारनाथ तक रोपवे निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान की है। इस अवसर श्रीमती गीता पुष्कर धामी, विधायक श्रीमती आशा नौटियाल, डॉ. मधु भट्ट, कर्नल अजय कोठियाल, तीर्थ पुरोहित श्रीनिवास पोस्ती, अंकित सेमवाल, उमेश पोस्ती हिमांशु चमोली एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलते ही हुई विशेष पूजा अर्चना

भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव

डोली शीतकाल गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर, उखीमठ से होते हुए गुप्तकाशी, फाटा, गौरीकुंड जैसे विभिन्न पड़ावों से श्री केदारनाथ धाम पहुंची। कपाट खुलने की प्रक्रिया सुबह पांच बजे से शुरू हुई। 6 बजे श्री केदारनाथ धाम के रावल भीमाशंकर लिंग, पुजारी बागेश लिंग, विधायक केदारनाथ आशा नौटियाल, जिलाधिकारी सौरभ गहरवार, बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल, तीर्थ पुरोहित श्रीनिवास पोस्ती, धर्माचार्यों वेदपाठीगणों भैरवनाथ के अरविंद शुक्ला ने पूरब द्वार से मंदिर में प्रवेश किया तथा मंदिर के गर्भगृह के द्वार की पूजा-अर्चना में शामिल हुए। कपाट खुलने के अवसर पर श्रीमती गीता धामी, जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह, मुख्य कार्याधिकारी बीकेटीसी विजय प्रसाद थपलियाल, पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे, मंदिर समिति प्रभारी अधिकारी/सहायक अभियंता गिरीश देवली, केदारसभा अध्यक्ष राजकुमार तिवारी धर्माधिकारी औंकार शुक्ला वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी यदुवीर पुष्पवान, पुजारी बागेश लिंग, वेदपाठी स्वयंबर सेमवाल, यशोधर मैठाणी, विश्व मोहन जमलोकी, देवानंद गैरोला, विपिन तिवारी कुलदीप धर्म्वाण, प्रकाश पुरोहित, उमेश शुक्ला सहित बड़ी संख्या में तीर्थ पुरोहित एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

चारों धामों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 23 लाख से ज्यादा हुआ

चारों धामों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 23 लाख से ज्यादा पहुंच गया है। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पहले दिन केदारनाथ धाम में 30154 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। जबकि यमुनोत्री धाम में 2 मई तक 29544 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। गंगोत्री धाम में 2 मई को 17362 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस तरह से अब तक तीनों धाम के कपाट खुलने पर 77050 यात्री दर्शन के लिए पहुंचे हैं। शुक्रवार को एक ही दिन में चारों धामों के लिए 9895 तीर्थ यात्राओं ने ऑफलाइन पंजीकरण भी कराया है। अब तक कुल 57,284 श्रद्धालु ऑफलाइन पंजीकरण करा चुके हैं। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2 मई शाम तक 23 लाख 50 हजार 845 यात्रियों के पंजीकरण हो चुके हैं। पर्यटन विभाग की ओर से ऋषिकेश, हरिद्वार, हरबर्टपुर और विकास नगर में भी ऑफलाइन पंजीकरण केंद्र खोले गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या केदारनाथ धाम के लिए है। यहां 7,92,312 श्रद्धालुओं ने दर्शन के लिए पंजीकरण कराया है। जबकि

केदारनाथ धाम पहुंचे सीएम धामी ने कहा- *इस बार भी चार धाम यात्रा नया कीर्तिमान बनाएगी*

रुद्रप्रयाग स्थित विश्व प्रसिद्ध ग्यारहवें ज्योर्तिलिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार सुबह सात बजे विधि-विधान से खुल गए हैं। कपाट उद्घाटन के लिए केदारनाथ मंदिर की भव्य सजावट की गई। मंदिर को 108 क्विंटल से अधिक फूलों से सजाया गया। भव्य सजावट के बीच कपाट खुलते ही हेली से पुष्प वर्षा भी की गई, जिसे देख श्रद्धालु अभिभूत नजर आए। कपाट खोलने के मौके पर केदारनाथ धाम भक्तों की भीड़ से पटा नजर आया। हर तरफ 'जय बाबा केदार' और 'बम-बम भोले' की गूंज सुनाई दी। जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भी रिकॉर्ड बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कपाट खुलने के साक्षी बने। मुख्यमंत्री ने कपाट खुलने पर केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना कर प्रदेश में सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। केदारनाथ धाम में सबसे पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम सम्पन्न हुई। मुख्यमंत्री धामी ने कपाट खुलने पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा राज्य के साथ ही संपूर्ण देश को इस पल की प्रतीक्षा रहती है। केदारनाथ धाम सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र होने के साथ ही भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। हमारे राज्य के लिए यह उत्सव का समय है। मुख्यमंत्री ने बाबा केदार से सभी यात्रियों के मंगलमयी यात्रा की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा केदार के धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। बाबा केदार के आशीर्वाद से इस वर्ष भी चारधाम यात्रा नया कीर्तिमान बनाएगी। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने चार धाम यात्रा के सुव्यस्थित और सफल संचालन के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा सुरक्षा और सुगमता के लिए सरकार ने सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। उन्होंने कहा हम सभी उत्तराखंडवासियों का कर्तव्य है कि हम देश और दुनिया से आने वाले अतिथियों का स्वागत आत्मीयता और सेवा भाव से करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ के अनन्य भक्त हैं। 2013 आपदा के बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केदार नगरी के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ। उन्हीं के मार्गदर्शन में आज केदारनाथ परिसर का दिव्य और भव्य निर्माण कार्य हुआ है। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ की इसी भूमि से 21वी सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक बताया था। उनके शब्दों को सच करने के लिए राज्य सरकार निरंतर विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है।

सीएम धामी केदारनाथ धाम पहुंचे

बद्रीनाथ धाम के लिए 7 लाख 11 हजार 434 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। इसी तरह गंगोत्री धाम के लिए 4 लाख 19 हजार 180 और यमुनोत्री धाम के लिए 3 लाख 84 हजार 52 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण किया है।

इस बार चार धाम यात्रा के दौरान धामी सरकार ने किए बेहतर प्रबंध

इस बार चार धाम यात्रा के दौरान प्रदेश की धामी सरकार ने श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो इसके लिए बेहतर प्रबंध किए हैं। इस साल चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को टोकन सिस्टम के जरिए दर्शन कराए जा रहे हैं। ऐसा भीड़ को मैनेज करने के लिए किया जा रहा है। इससे श्रद्धालुओं को भी घंटों लाइन में लगने से छुटकारा मिलेगा। तीर्थयात्रियों को धाम पहुंचने पर उनके यात्रा पंजीकरण के आधार पर एक टोकन दिया जाएगा। इस टोकन में स्पष्ट रूप से दर्शन का समय दर्ज होगा, जिसके अनुसार वे दर्शन कर सकेंगे। टोकन सिस्टम कैसे करेगा काम। चारधाम यात्रा से पहले श्रद्धालु को पंजीकरण कराना जरूरी है। धाम पहुंचने पर पंजीकरण दिखाने के बाद ही टोकन मिलेगा। टोकन में दर्शन का समय तय होगा। श्रद्धालु उस समय के अनुसार सीधे दर्शन कर सकेंगे। इस बार चारधाम यात्रा के दौरान मंदिर परिसर में वीडियो रील्स बनाने वालों को नहीं आने दिया जाएगा। यात्रा के दौरान यदि कोई सोशल मीडिया रील बनाता मिला तो बिना दर्शन उसे लौटा दिया जाएगा। बताया जाता है कि चारधाम की प्रकृति के लिए ये शोर शराबा ठीक नहीं है इसलिए इस बार कैमरा ऑन भी नहीं करने दिया जाएगा। इस बार चारधाम यात्रा के दौरान पैसे देकर वीआईपी दर्शन की व्यवस्था भी सभी धामों पर बंद रहेगी। बद्रीनाथ धाम की पंडा पंचायत का कहना है कि ये पैसे लेकर दर्शन करवाना भगवान की मर्यादा के खिलाफ है। इस बार सभी श्रद्धालु सामान्य दर्शन ही कर पाएंगे। इससे सभी को दर्शन करने का समान मौका मिलेगा। चारधाम यात्रा मार्ग को 10-10 किलोमीटर के हिस्सों में बांटा गया है। हर हिस्से में 6 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। यदि मौसम खराब होता है, तो यात्रियों को राहत देने के लिए 10 जगहों पर होल्डिंग स्थल बनाए गए हैं। यहां पर खाने-पीने और दूसरी जरूरी चीजें मिलेंगी। चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन पास के चेक प्वाइंट्स बनाए गए हैं। यमुनोत्री में बड़ाकोट, गंगोत्री में हीना, केदारनाथ में सोनप्रयाग और बद्रीनाथ में पांडुकेश्वर में चेक प्वाइंट्स बनाए गए हैं।

पाकिस्तान पर हमले का इंतजार कर रहा पूरा देश

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देशवासी रोजाना रात में इस सोच में सोते हैं कि सवेरे पाकिस्तान पर हमले को लेकर कोई बड़ी खबर आएगी। लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 12 दिन बीतने के बाद अभी तक भारत ने पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया है। वहीं पाक भी भारत के हमले से थर्राया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में एक हाईलेवल की मीटिंग की। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुखों सहित शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों से कहा- उन्हें आतंकवाद से निपटने के लिए खुली छूट है। पहलगाम हमले का करारा जवाब देना राष्ट्रीय संकल्प है।

22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देशवासी रोजाना रात में इस सोच में सोते हैं कि सवेरे पाकिस्तान पर हमले को लेकर कोई बड़ी खबर आएगी। लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 12 दिन बीतने के बाद अभी तक भारत ने पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया है। वहीं पाकिस्तान भी भारत के हमले से थर्राया हुआ है। साल 1991 में बॉलीवुड निर्देशक सुभाष गई की फिल्म 'सौदागर' आई थी। इस फिल्म में अभिनेता राजकुमार का एक संवाद जो पूरे देश भर में प्रसिद्ध हुआ था। जिसके बोल थे, 'हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे लेकिन तब जब वक्त हमारा होगा... इसी डायलॉग के तर्ज पर केंद्र सरकार भी पाकिस्तान को यही संदेश दे रही है। इन सबके बीच देशवासी पाकिस्तान को जल्द करारा जवाब देने का इंतजार कर रहे हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में एक हाई लेवल की मीटिंग की।

इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुखों सहित शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान भी शामिल हुए। यह बैठक पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में भारत द्वारा उठाए जाने वाले संभावित कदमों पर विचार किए जाने के बीच हुई। पीएम मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों से कहा- उन्हें आतंकवाद से निपटने के लिए खुली छूट है। पहलगाम हमले का करारा जवाब देना राष्ट्रीय संकल्प है। पहलगाम के लोकप्रिय पर्यटन स्थल बैसरन में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में कम से कम 26 लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकतर पर्यटक थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हमले में शामिल आतंकवादियों और उनके आकाओं का ''पृथ्वी के अंतिम छोर तक'' पीछा करने और उन्हें ''उनकी कल्पना से परे'' कड़ी से कड़ी सजा देने का आहवान किया है। पहलगाम हमला जम्मू-कश्मीर में नागरिकों पर पिछले कई वर्षों में हुआ सबसे घातक हमला है, जिसे लेकर पूरे देश में आक्रोश की लहर है और हमलावरों तथा उनके आकाओं के खिलाफ कठोर जवाबी कार्रवाई की मांग उठ रही है। प्रधानमंत्री की कठोर टिप्पणियों और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर उनकी सरकार के कड़े रुख के कारण भारत की ओर से करारी जवाबी कार्रवाई की उम्मीदें बढ़ गई हैं। मोदी सरकार ने 2016 में उरी में सेना के जवानों पर आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के अंदर 'सर्जिकल स्ट्राइक' की थी। उसने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाए जाने के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमला किया था। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए हैं, जिनमें पड़ोसी देश के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करना भी शामिल है।

ओवैसी बोले- पीओके में कब्जा करे भारत, अमित शाह ने कहा- आतंकियों को उखाड़ फेकेंगे

पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की बेरहमी से हत्या के बाद पूरा देश गुस्से में है। इस गर्म माहौल में सबसे अधिक हैरान हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने किया। ओवैसी ने

पाकिस्तान पर हमला करने को लेकर मोदी सरकार का पूरा समर्थन किया है। 'ओवैसी ने कहा कि इस बार पीओके (पाक अधिकृत कश्मीर) पर कब्जा कर लो यह क्षेत्र हमारा है।'

भारतीय राजनीति के मुस्लिम चेहरा बने ओवैसी ने न सिर्फ पाकिस्तान पर हमला बोला, बल्कि पाकिस्तानी नेताओं के बेशर्म बयानों का करारा जवाब दिया। पहलगाम आतंकी हमले से पहले तक असदुद्दीन ओवैसी भारतीय राजनीति में मुसलमानों के नुमाइंदे के तौर पर पहचाने जाते रहे। उनके विरोधी उन पर सांप्रदायिक और विभाजनकारी होने का आरोप लगाते रहे हैं। हाल ही वक्फ संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान संसद में उन्होंने बिल की कॉपी फाड़कर गुस्से इजहार किया था। अपनी जनसभाओं में जब वह हैदराबादी लहजे में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को सीधी चुनौती देते हैं, तो मुसलमान तालियां पीटते हैं। पहलगाम हमले के बाद उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और भारत में हिंदू-मुसलमान में विभाजन की नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया। ओवैसी ने राष्ट्रवादी लहजे में जिस तरह अपनी आवाज बुलंद की, उसके सामने कई हिंदू नेता फीके पड़ गए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश में एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छुट दे दी है और उन्हें अपने हिसाब से टारगेट सेट करने की छूट है। ओवैसी ने कहा, बीजेपी कहती है 'घर में घुस के मारेंगे', तो अगर इस बार कार्रवाई कर रहे हैं, तो 'घर में घुस के बैठ जाना'। ये संसद का प्रस्ताव है कि गुलाम कश्मीर हमारा हिस्सा है। अगर यह बात सरकार मानती है, तो फिर उसे जमीनी स्तर पर दिखना भी चाहिए। बार-बार टेररिस्ट अटैक नहीं होना चाहिए। यह भारतीय संसद का संकल्प है कि पीओके हमारा है। सभी विपक्षी दल सरकार से कह रहे हैं कि आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए।

वहीं पहलगाम हमले के बाद भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी कीमत पर आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में कहा कि आतंकवाद को जड़ समेत उखाड़

फेकेंगे।

पाक के साथ तनातनी के बीच भारत ने फ्रांस से 26 राफेल विमान की डील की

पहलगाम में आतंकी अटैक के बाद भारत की पाकिस्तान के साथ जंग जैसे हालात हैं। दोनों देशों के बीच बॉर्डर भी सील कर दिए गए हैं। इस बीच भारत, फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन विमानों की डील सोमवार को साइन हो गई। डील के तहत भारत, फ्रांस से 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। ये विमान परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के साथ ये डील करीब 63,000 करोड़ रुपए में हो रही है। हथियारों की खरीद के मामले में यह फ्रांस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील है। विमानों की खरीद को 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में मंजूरी मिली थी। यह मीटिंग पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद बुलाई गई थी। भारत इससे पहले 2016 में भी फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान एयरफोर्स के लिए खरीद चुका है। यह डील 58,000 करोड़ रुपए की थी और अंतिम विमान 2022 तक भारत पहुंच चुके हैं, जिन्हें अंबाला और हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किया गया है। राफेल मरीन विमान उन्हीं राफेल एयरफोर्स वर्जन से तकनीकी रूप से और अधिक एडवांस हैं। इन विमानों को युद्ध पोत पर तैनात करने के हिसाब से ही डिजाइन किया गया है। फ्रांस की सेना पहले से ही इनका इस्तेमाल कर रही है। भारत के पास पहले से ही 36 राफेल विमान हैं। 2016 में ही इन विमानों के लिए फ्रांस की कंपनी के साथ डील हुई थी। नई डील के बाद भारत में राफेल की संख्या बढ़कर 62 हो जाएगी। राफेल-एम सिर्फ एक मिनट में 18 हजार मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। यह पाकिस्तान के एफ-16 और चीन के जे-20 से ज्यादा बेहतर है। यह उड़ान भरने के बाद 3700 किमी दूर तक हमला करने में सक्षम है। इसमें 30 एमएम की ऑटो कैनन गन और 14 हार्ड प्वाइंट्स हैं। यह बहुत कम जगह पर भी 'लैंड' कर सकता है। राफेल-एम में शक्तिशाली एंटी शिप मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम हैं। यह विमान पनडुब्बियां खोजकर ध्वस्त करने वाले विशेष रडार से लैस होता है। खास बात यह है कि राफेल-एम में बीच हवा में ही रीफ्यूलिंग की जा सकती है। इससे इसकी रेंज और बढ़ जाएगी। इसकी पहली खेप 3 साल बाद मिलनी शुरू होगी।

पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान के 16 यूटयूब चौनलों को किया बैन

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार लगातार पाकिस्तान पर आर्थिक से लेकर कई मुद्दों पर प्रतिबंध लगा रही है। दोनों देशों में तनाव जारी है। कई दिनों से एलओसी पर पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है। भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया भारत के बारे में अफवाह फैला रही थी, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने पाकिस्तानी मीडिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी बैन कर दिया है। इसके बाद से कोई भी पाकिस्तानी मीडिया चैनल भारत में शो नहीं कर रहा है। केंद्र सरकार ने कार्रवाई करते हुए कई पाकिस्तानी यूटयूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले के साथ ही भारतीय यूटयूब यूजर्स के लिए शोएब अख्तर, आरजू काजमी और सैयद मुजम्मिल शाह जैसे पाकिस्तानी चैनलों तक पहुंच प्रतिबंधित कर दी गई है। गृह मंत्रालय की सिफारिशों पर भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर में दुखद पहलगाम आतंकी घटना की पृष्ठभूमि में भारत, उसकी सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे और भ्रामक आख्यान और गलत सूचना प्रसारित करने के लिए डॉन न्यूज, समा टीवी, आर्य न्यूज, जियो न्यूज सहित 16 पाकिस्तानी यूटयूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत सरकार ने इस पर सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक एक्स (पहले ट्विटर) अकाउंट सहित कई पाकिस्तानी चैनलों के सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लॉक कर दिया है। अब भारतीय यूजर्स पाकिस्तान सरकार या मीडिया के सोशल मीडिया पेज नहीं देख सकेंगे। यह फैसला सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए लिया गया है। भारत ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रविरोधी और दुष्प्रचार फैलाने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उत्तराखंड का भू-कानून 2025 लागू, आंशिक विजय

विडंबना है कि राज्य गठन के 25 वर्ष बाद भी जनता को अपनी जमीन, संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है।

शीशपाल गुसाई

हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक वैभव के लिए विश्वविख्यात है। किंतु इस पवित्र भूमि की पहचान केवल इसकी प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा तक सीमित नहीं है! यह एक ऐसी धरती है, जहां की जनता ने अपनी अस्मिता, अधिकारों और संसाधनों की रक्षा के लिए बार-बार आंदोलनों का दामन थामा है। हाल ही में लागू हुआ उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2025, जिसे राज्यपाल की मुहर प्राप्त होने के पश्चात् 1 मई, 2025 को प्रभावी किया गया, एक बार फिर इस सतत संघर्ष की गवाही देता है। यह भू-कानून, जो प्रदेश के 11 पर्वतीय जिलों में गैर-नगरीय क्षेत्रों में बाहरी लोगों द्वारा 250 वर्ग मीटर से अधिक कृषि भूमि खरीद पर रोक लगाता है, न केवल एक प्रशासनिक निर्णय है, बल्कि उत्तराखंड की जनता के दशकों लंबे आंदोलन का परिणाम भी है। किंतु सवाल यह है कि क्या यह कानून वास्तव में पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं को पूर्ण करता है, अथवा यह एक अधूरी विजय है, जो बार-बार आंदोलन की आवश्यकता को रेखांकित करती है?

भू-कानून का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और वर्तमान स्वरूप

उत्तराखंड के गठन के समय से ही भू-कानून एक ज्वलंत मुद्दा रहा है। 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर बने इस राज्य में शुरूआती दौर में भूमि खरीद पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं था। परिणामस्वरूप, बाहरी लोगों ने, विशेषकर पर्यटन और रियल एस्टेट के आकर्षण के चलते, पहाड़ों की बेशकीमती जमीनों को सस्ते दामों में खरीदना शुरू किया। स्थानीय लोग, जो अपनी आजीविका के लिए इन जमीनों पर निर्भर थे, धीरे-धीरे भूमिहीन होने लगे। 2003 में तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार ने बाहरी लोगों के लिए आवासीय उपयोग हेतु 500 वर्ग मीटर भूमि खरीद की सीमा तय की, जिसे 2008 में बी.सी. खंडूड़ी सरकार ने घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया। किंतु ये नियम नगरीय क्षेत्रों पर लागू नहीं थे, जिसके कारण देहरादून, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल, जैसे शहरों के आसपास की जमीनें बड़े पैमाने पर बाहरी लोगों के हाथों में चली गई। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने 2018 में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन कर उद्योगों के लिए जमीन खरीद की बाध्यताओं को हटा दिया, जिससे बाहरी लोगों को अधिक जमीन खरीदने की छूट मिली। इस निर्णय ने व्यापक विरोध को जन्म दिया और मूल निवास 1950 की मांग को और बल मिला।

2025 का भू-कानून, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने पहले कैबिनेट में मंजूरी दी और फिर विधानसभा के बजट सत्र में पारित करवाया, एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर को छोड़कर शेष 11 पर्वतीय जिलों में बाहरी लोग कृषि और बागवानी भूमि नहीं खरीद सकेंगे। आवासीय उपयोग के लिए भी 250 वर्ग मीटर की सीमा तय की गई है, जिसके लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित उद्देश्य से इतर भूमि का उपयोग करता है, तो वह सरकार में निहित हो जाएगी। यह कानून निश्चित रूप से स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग का परिणाम है, किंतु इसकी सीमाएं भी स्पष्ट हैं। नगरीय क्षेत्रों को इस कानून के दायरे से बाहर रखने और हरिद्वार-ऊधम सिंह नगर जैसे मैदानी जिलों को छूट देने से यह आंशिक रूप से प्रभावी प्रतीत होता है।

नरेंद्र सिंह नेगी और जन-आंदोलन की चिंगारी

उत्तराखंड की सांस्कृतिक आत्मा को अपनी गीतों में पिरोने वाले लोकप्रिय गढ़वाली गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने 2023, 2024 में भू-कानून के समर्थन में अपने गीतों के माध्यम से जनता को सड़कों पर उतरने का आहवान किया। उनके गीत, जो पहाड़ की पीड़ा, संस्कृति और संघर्ष को व्यक्त करते हैं, उत्तराखंड के युवाओं और स्थानीय लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गए। देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, कोटद्वार, रामनगर जैसे शहरों में आंदोलनकारियों ने सशक्त भू-कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन किए, जो 1994 के उत्तराखंड राज्य आंदोलन की तर्ज पर थे। नेगी के गीतों ने न केवल जनमानस को जागृत किया, बल्कि यह भी रेखांकित किया कि

पहाड़ की अस्मिता और संसाधनों की रक्षा के लिए एकजुटता आवश्यक है। उनके गीतों में छिपी पीड़ा यह थी कि बाहरी लोगों द्वारा अंधाधुंध भूमि खरीद ने पहाड़ के मूल स्वरूप को खतरे में डाल दिया है।

पर्वतीय जनता के भाग्य में आंदोलन ही आंदोलन

उत्तराखंड की जनता का इतिहास आंदोलनों से भरा पड़ा है। 1970 के दशक में शुरू हुआ चिपको आंदोलन, जिसने पर्यावरण संरक्षण की वैश्विक मिसाल कायम की, हो या 1994 का उत्तराखंड राज्य आंदोलन, जिसने अलग राज्य की मांग को साकार कियाकृपर्वतीय जनता ने अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए हमेशा सड़कों का सहारा लिया। किंतु यह विडंबना है कि राज्य गठन के 25 वर्ष बाद भी जनता को अपनी जमीन, संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। इसका एक प्रमुख कारण है प्रशासनिक मशीनरी की उदासीनता और कुछ हद तक स्थानीय लोगों की निष्क्रियता। जैसा कि लेख में उल्लेख किया गया है, कई लोगों का मानना है कि यदि स्थानीय प्रशासन बाहरी लोगों के साथ सांठ-गांठ न करता, तो इतने बड़े पैमाने पर जमीनों की खरीद-फरोख्त संभव न होती। पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि की कमी और वहां की भौगोलिक परिस्थितियां इसे और जटिल बनाती हैं। केवल 13.92: मैदानी और 86: पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण कृषि भूमि पहले से ही सीमित है। बाहरी लोगों द्वारा होटल, रिसॉर्ट और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन खरीदने से न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा, बल्कि स्थानीय लोगों की आजीविका भी खतरे में पड़ गई।

किंतु, जैसा कि पर्यावरणविद् रवि चोपड़ा, राज्य वरिष्ठ पत्रकार व लेखक जय सिंह रावत ने कहा, 'राज्य की हर सरकार ने लोगों को धोखा ही दिया है।' नगरीय क्षेत्रों को इस कानून से बाहर रखना और हरिद्वार-ऊधम सिंह नगर जैसे जिलों को छूट देना इस कानून की सबसे बड़ी कमी है। देहरादून जैसे शहरों में नगर निगम की सीमा का विस्तार होने से आसपास के गांव अब नगरीय क्षेत्रों में शामिल हो चुके हैं, जिसके कारण वहां भूमि खरीद पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता। यह एक अधूरी पाबंदी है, जो भविष्य में और सशक्त कानून की मांग को जन्म दे सकती है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की जनता के भाग्य में आंदोलन ही आंदोलन क्यों लिखा है? इसका उत्तर इस तथ्य में निहित है कि जब तक नीतियां और कानून जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप और पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होंगे, तब तक संघर्ष अनिवार्य रहेगा। हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर एक सशक्त भू-कानून, जो न केवल पर्वतीय क्षेत्रों, बल्कि समस्त उत्तराखंडकृनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रोंकृपर लागू हो, ही इस समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते है। डिजिटल पोर्टल के माध्यम से बाहरी लोगों द्वारा खरीदी गई प्रत्येक इंच जमीन का रिकॉर्ड रखा जाए, जैसा कि सरकार ने प्रस्तावित किया है। गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए कृषि भूमि के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। नरेंद्र सिंह नेगी जैसे सांस्कृतिक प्रतीकों के माध्यम से जनता को अपनी जमीन और संस्कृति की रक्षा के लिए प्रेरित किया जाए।

जब तक नगरीय क्षेत्रों और मैदानी जिलों को इसके दायरे में नहीं लाया जाता, तब तक यह आंशिक विजय ही रहेगी। उत्तराखंड की जनता का इतिहास बताता है कि वह अपनी अस्मिता और अधिकारों के लिए चुप नहीं बैठती। चिपको से लेकर राज्य आंदोलन और अब भू-कानून तक, यह धरती संघर्ष की धरती रही है। शायद यही इसकी नियति हैकृसंघर्ष के माध्यम से अपनी पहचान को संरक्षित करना। किंतु यह भी सच है कि जब तक शासन-प्रशासन और जनता में पूर्ण समन्वय और जागरूकता नहीं होगी, तब तक यह सिलसिला थमेगा नहीं।

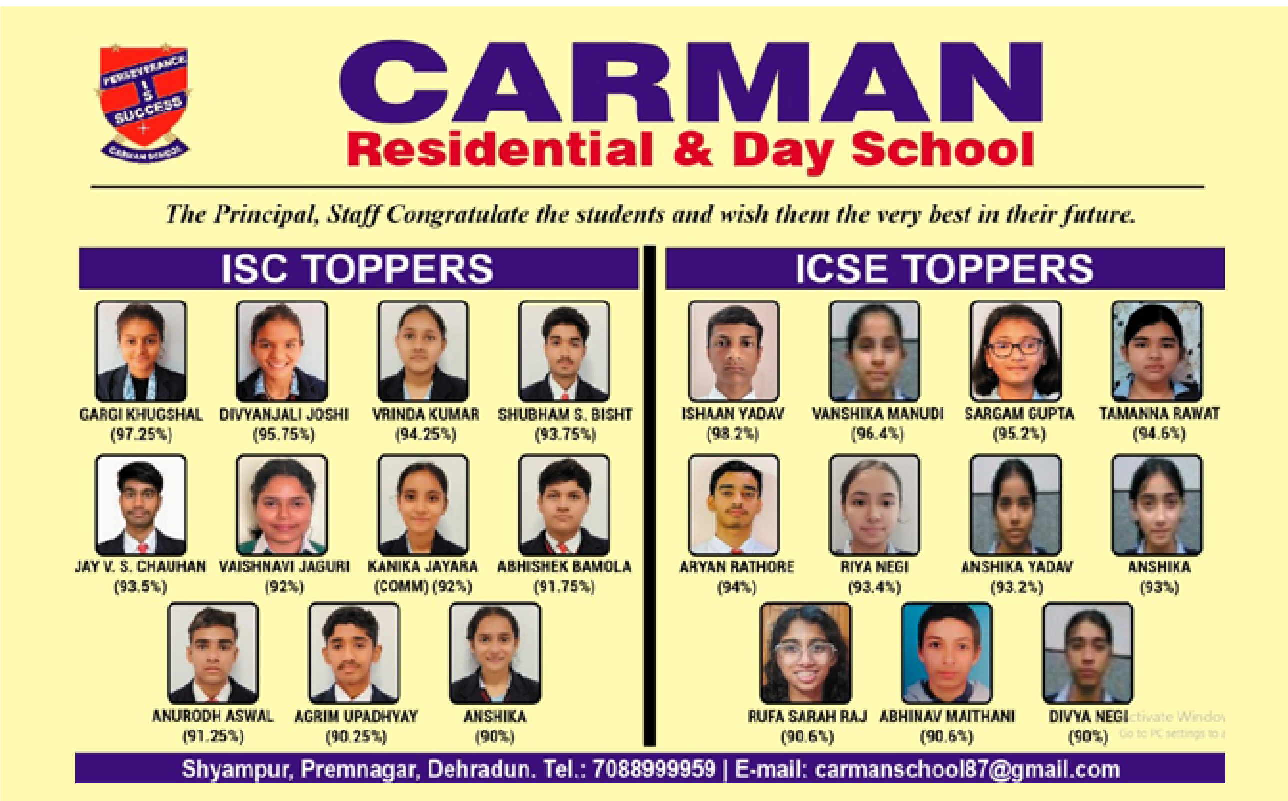

जाति जनगणना विभाजन का नहीं, विकास का आधार बने

ललित गर्ग

पहलगाम की क्रूर एवं बर्बर आतंकी घटना के बाद मोदी सरकार लगातार पाकिस्तान को करारा जबाव देने की तैयारी के अति जटिल एवं संवेदनशील दौर में एकाएक जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लेकर न विपक्षी दलों को बल्कि समूचे देश को चौकाया एवं चमत्कृत किया है। सरकार का यह निर्णय जितना बड़ा है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। मोदी सरकार का जातिगत जनगणना के लिए तैयार होना सुखद और स्वागतयोग्य है। पिछले कुछ समय से जातिगत जनगणना की मांग बहुत जोर-शोर से हो रही थी। कुछ राज्यों में तो भाजपा भी ऐसी जनगणना के पक्ष में दिखी थी, पर केंद्र सरकार का रुख इस पर बहुत साफ नहीं हो रहा था। अब अचानक ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राजनीतिक मामलों की उच्चस्तरीय कैबिनेट समिति की बैठक में यह फैसला ले लिया गया। बाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि आगामी जनगणना में जातिगत गणना भी शामिल रहेगी। यह कदम जहां देश के राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को बदलेगा, वही सामाजिक असमानताओं को दूर करने और वंचित समुदायों के उत्थान के लिए लक्षित नीतियों को लागू करने में मील का पत्थर साबित होगा।

जातिगत जनगणना 1931 यानी अखंड भारत में अंग्रेजी सत्ता ने कराई थी। भारत में जनगणना की शुरुआत अंग्रेजी हुकूमत के दौर में, सन 1872 में हुई थी और 1931 तक हुई हर जनगणना में जाति से जुड़ी जानकारी को भी दर्ज किया गया। आजादी के बाद सन् 1951 में जब पहली बार जनगणना कराई गई, तो तय हुआ कि अब जाति से जुड़े आंकड़े नहीं जुटाए जाएंगे। स्वतंत्र भारत में हुई जनगणनाओं में केवल अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े डेटा को ही पब्लिश किया गया। 2011 में मनमोहन सरकार ने जातिवार जनगणना कराई अवश्य, लेकिन उसमें इतनी जटिलताएं एवं विसंगतियां मिलीं कि उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। इसके बाद कुछ राज्यों ने जातियों की गिनती करने के लिए सर्वे कराए, क्योंकि जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र को ही है। हालांकि भाजपा ने बिहार में जाति आधारित सर्वे का समर्थन किया, लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर वह मुखर नहीं रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अवश्य इसका समर्थन किया। लेकिन अब एकाएक भाजपा को जातिगत जनगणना करना अपने हित में दिखाई दिया क्योंकि अपनी नीतियों एवं योजनाओं के बल पर भाजपा ने पिछड़ी जातियों और दलितों की गोलबंदी कर सत्ता का सफर आसान बनाया है।

जातिगत जनगणना का भारतीय राजनीति और समाज-व्यवस्था पर व्यापक एवं दूरगामी प्रभाव पडेगा। कांग्रेस और कुछ क्षेत्रीय दल इसकी पुरजोर मांग करने में लगे हुए थे। सबसे ज्यादा जोर राहुल गांधी दे रहे थे, जबकि नेहरू से लेकर नरसिंह राव तक ने इसकी जरूरत नहीं समझी। यह तय है कि जातिगत जनगणना कराने के फैसले पर जहां कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दल इसका श्रेय लेना चाहेंगे, वहीं भाजपा इसे सामाजिक न्याय एवं समता-संतुलित समाज-निर्माण केंद्रित अपनी पहल बताएगी। जाति आधारित जनगणना सामाजिक न्याय में सहायक बनेगी या नहीं, लेकिन इससे जातिवादी राजनीति के नए दरवाजे खुलेंगे एवं आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर राजनीति की धूरी बनेगा। कांग्रेस एवं विपक्षी दलों ने अपने संकीर्ण एवं स्वार्थी राजनीतिक नजरिये से यह मांग इसलिए उठाई थी ताकि इस आधार पर आगे आरक्षण के मुद्दे को गर्माया जा सके और जातीय गोलबंदी कर चुनावी फायदा लिया जा सके। लेकिन भाजपा-सरकार ने जाति जनगणना का ऐलान कर इस मुद्दे को अपनी पाली में ले लिया है। भले ही इसके आंकड़े आने के बाद आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग से भाजपा कैसे निपटेगी, यह बड़ी चुनौती उसके सामने है। वैसे भी इस तरह की पहल जिन राज्यों में हुई है, वहां भी इसे लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे विवाद भाजपा के लिये एक नयी चुनौती बनेंगे। जाति आधारित जनगणना से भारतीय समाज के नये कोने-अंतरे-चुनौतियां सामने आयेगी। लेकिन जातिगत जनगणना के समर्थकों का मानना है कि यह सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। जनगणना में दलितों और आदिवासियों की संख्या तो गिनी जाती है और उन्हें राजनीतिक आरक्षण भी मिला हुआ है लेकिन पिछड़ी और अति पिछड़ी (ओबीसी और ईबीसी) जातियों के कितने लोग देश में हैं इसकी गिनती नहीं होती है।

जनगणना एक बहुत बड़ी कवायद है और अगर इसमें जातिगत गणना को भी शामिल किया जा रहा है, तो काम और भी सावधानी एवं सतर्कता से करना होगा। हजारों जातियां

हैं और उनकी हजारों उप-जातियां हैं। सबको अलग-अलग गिनने के लिए देश को अपनी डिजिटल शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। निश्चित ही नयी राजनीतिक एवं नीतिगत स्थितियां समस्याएं खड़ी होंगी। अब सभी जातियों की गिनती होगी। यह गिनती मुस्लिम, ईसाई और अन्य समुदायों में भी होनी चाहिए, क्योंकि कोई दावा कुछ भी करे, जाति और उसके आधार पर विभेद सब जगह है। इससे भी ज्यादा आवश्यक, बल्कि अनिवार्य यह है कि जातिगत जनगणना जातिवाद की राजनीति का हथियार न बने और वह भारतीय समाज को विभाजित न करने पाए। इस अंदेशे को दूर करने के कुछ ठोस उपाय होने ही चाहिए कि जाति आधारित जनगणना जातीय विभाजन का कारण न बनने पाए। यह अंदेशा इसलिए है, क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं कि कई राजनीतिक दल खुले रूप से जाति की राजनीति करते हैं। माना जाता है कि देश की आबादी में 52 फ़ीसदी लोग पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के हैं। ओबीसी समुदाय के नेताओं का मानना है कि इस हिसाब से उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी काफ़ी कम है। राजनीतिक दल इन समुदायों का समर्थन हासिल करने के लिए जाति जनगणना का समर्थन कर रहे हैं। भारत में जाति जनगणना आजादी के बाद रुकी, पर अब सामाजिक न्याय, नीतिगत सुधार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए इसकी जरूरत महसूस की जा रही है। पारदर्शिता और सावधानी से किया गया यह कदम समावेशी विकास का आधार बन सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जाति आधारित जनगणना को एक समतामूलक समाज निर्माण के दृष्टिकोण से समर्थन देने के संकेत दिए हैं। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि यह संवदेनशील मामला है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक या चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं बल्कि पिछड़ रहे समुदाय और जातियों के कल्याण के लिए होना चाहिए। जाति जनगणना के आंकडे प्रस्तुत होने से राजनीति और ब्यूरोक्रेसी में पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की हिस्सेदारी कितनी कम है, यह डर संभवत: भाजपा को सता रहा था। लेकिन भाजपा का यह डर या तो ख़त्म हो गया है, या फिर उसने बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में चुनावी लाभ लेने के लिए ये क़दम उठाया है। भाजपा इसके ख़िलाफ़ थी, उसने जातिगत जनगणना को देश को बांटने की कोशिश करने वाला बताया था। लेकिन एनडीए में शामिल भाजपा की ज्यादातर सहयोगी पार्टियां इसके पक्ष में हैं।

जातिगत जनगणना के आंकड़े 2026 या 2027 के अंत में आएंगे और तब तक बिहार और यूपी के चुनाव हो चुके होंगे। इसलिए इसका चुनावी लाभ लेने की बात सही नहीं है। वैसे भी भाजपा ने हाल के वर्षों में पिछड़ों और दलितों समुदाय को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की है। भाजपा इस जातिगत गणना से ये भी दिखाना चाहती है कि पिछड़ों के एक-आध समुदाय को छोड़ दें तो ओबीसी समुदाय का बड़ा हिस्सा उसके साथ है। वैसे तो विभिन्न राजनीतिक दल अमुक-अमुक जातियों का नेतृत्व करने के लिए केवल जाने ही नहीं जाते, बल्कि ऐसा दावा भी करते हैं। इसलिये जाति आधारित जनगणना का लाभ है तो हानि भी है। इससे बेहतर और कुछ नहीं कि जातिगत जनगणना वंचितों-पिछड़ों के उत्थान में सहायक बने, लेकिन यदि वह विभाजन को बल देती है और देश की एकजुटता प्रभावित करती है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं होगा। जनगणना के आंकड़े सरकार और जनता के लिए खुले और पारदर्शी होने चाहिए, ताकि सामाजिक संबंधों, आर्थिक अवसरों और राजनीतिक गतिशीलता की नई एवं समानतामूलक दिशाएं उद्घाटित हो सके और भारतीय समाज की विविधता की एक व्यापक सकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत की जा सके। कोई भी आंकड़ा तभी सराहनीय है, जब उससे विकास तेज करने में मदद मिलती हो, एक समतामूलक एवं संतुलित समाज की संरचना को बल मिलता हो।

इमेजिनेशन एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट में इंटेंजिबलिज्म यात्रा का आयोजन

देहरादून। सुभाष नगर स्थित इमेजिनेशन एकेडमी ऑफ़ फाइन आर्ट्स में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया जिसको अश्विनी कुमार पृथ्वी वासी एवं प्रशांत आर्य ने संबोधित किया जिसमें इनटेंजिबल आर्ट के माध्यम से अश्विनी कुमार पृथ्वी वासी ने कला को एक नई परिभाषा देते हुए वैश्विक आहवान और सामाजिक बदलाव के लिए इंगित किया है। ऐसे समय में जब कला का अधिकांश भाग व्यवसाय से जुड़ गया है प्रसिद्ध बहु आयामी कलाकार शिक्षाविद एवं दार्शनिक अश्विनी कुमार पृथ्वीवासी जी ने एक सशक्त व नई दार्शनिक अवधारणा प्रस्तुत की है इंटेंगिलिज्म तीन दशकों से अधिक प्रभावशाली यात्रा में लाखों जीवन को छूने वाले पृथ्वीवासी अब एक वैश्विक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं जो कला को सामाजिक परिवर्तन का सीधा माध्यम बनाने की दिशा में कार्यरत है इनटेंजियलिज्म पारंपरिक और बाजार केंद्रित कला की धारणा को चुनौती देता है पृथ्वीवासी ने बताया कि सच्ची कला केवल सौंदर्य एवं आर्थिक मूल्य तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि निस्वार्थ भावना और साहस से और क्रोध होनी चाहिए उनके जीवन शैली और कार्य इसी दर्शन को प्रत्यक्ष रूप से दर्शाते हैं उन्होंने 20 से अधिक आत्मनिधि पोषित योग परियोजना के माध्यम से जन जागरूकता मुक्त शिक्षा पर्यावरणीय पहला और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में व्यापक योगदान दिया है। वर्ष 2001 में उन्होंने पृथ्वीवासी नाम को कानूनी रूप से अपनाया जिसका अर्थ है पृथ्वी का निवासी उनका यह कदम जाति धर्म और राष्ट्रीयता जैसे सामाजिक विभाजनों के विरुद्ध एक सशक्त प्रतीक बन उन्होंने अपने बेटे का नाम भी अर्थीयन पृथ्वीवासी रखा ताकि यह विचार आने वाले पीढ़ियों तक पहुंचे।

धामी सरकार सख्त, मिलावटखोरी पर शिकंजा

यात्रियों की सेहत से खिलवाड नहीं सहेंगे: मुख्यमंत्री

चारधाम, मानसखंड, कैलास मानसरोवर यात्रा व पर्यटन सीजन को लेकर FDA अलर्ट मोड में

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार के निर्देश पर अपर आयुक्त ताजवर सिंह जग्गी के नेतृत्व में FDA टीम का हरिद्वार-हल्द्वानी व उधमसिंहनगर में ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान

चारधाम यात्रा, मानसखंड यात्रा, कैलास मानसरोवर यात्रा और आगामी पर्यटन सीजन को लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मिलावटखोरों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति पर काम हो रहा है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य सचिव व आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) डॉ. आर राजेश कुमार के निर्देश पर अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी के नेतृत्व में FDA की टीम कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के दौरे पर रवाना हो गई है। टीम ने अपने पहले दिन हरिद्वार से लेकर हल्द्वानी व उधमसिंहनगर तक ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया। अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने कहा आयुक्त डॉ. आर राजेश कुमार के निर्देश पर उनका यह दौरा मुख्य रूप से यात्रा मार्गों पर खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और नकली दवाओं की रोकथाम की तैयारियों की समीक्षा को लेकर है।

हरिद्वार-नजीबाबाद मार्ग पर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, चार ढाबों पर कार्रवाई

आज अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी एवं संयुक्त आयुक्त डॉ. आर.के. सिंह के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने हरिद्वार-नजीबाबाद मार्ग स्थित सजनपुर और चिडियापुर क्षेत्र के ढाबों व भोजनालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गम्भीर अनियमितताएं पाए जाने पर मामा भांजा गढ़वाली ढाबा, न्यू स्टार गढ़वाली ढाबा और हिमालयन भोजनालय के फूड लाइसेंस 7 दिन के लिए निलंबित कर दिए गए। इन ढाबों में खुले वॉशिंग एरिया, सड़ी-गली खाद्य सामग्री, खुले मसालों का उपयोग, गंदगी व बदबूदार किचन आदि प्रमुख कमियां पाई गई। वहीं सजनपुर स्थित खैरा पंजाबी ढाबा को आवश्यक दस्तावेज न देने और खाद्य सामग्री की गलत ढंग से स्टोरेज करने पर नोटिस जारी किया गया। सभी संचालकों को 7 दिन के भीतर सुधार कर अनुपालन रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर स्थायी लाइसेंस रद्द कर, एफएसएस एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

हल्द्वानी व उधमसिंहनगर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई

अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी और संयुक्त आयुक्त डॉ. आर.के. सिंह के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने हल्द्वानी और उधमसिंहनगर जनपदों में व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान खाद्य सामग्री विक्रेताओं, मिठाई दुकानों, होटल-ढाबों और मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की गई। टीम ने कई स्थानों पर साफ-सफाई में लापरवाही, एक्सपायरी उत्पादों की बिक्री, लाइसेंस की अनुपलब्धता और खाद्य मानकों के उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई। कई दुकानों को नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने व कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के निर्देश पर प्रदेश

प्रशासन, विशेषकर FDA, यात्रा मार्गो पर खाद्य और औषधि सुरक्षा को लेकर एक्शन मोड में है। स्वास्थ्य सचिव/ आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार के निर्देश पर अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी पूरी टीम के साथ दोनों मंडलों के दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरान निरीक्षण दलों के साथ बैठकें, स्थानीय व्यापारियों, ढाबा संचालकों, होटल मालिकों व आम नागरिकों से संवाद स्थापित भी किया जा रहा है। उनका उद्देश्य सभी को खाद्य सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि 'हमें सुनिश्चित करना है कि यात्रियों को स्वच्छ और मिलावटमुक्त खाद्य सामग्री मिले, ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित और सुखद हो।'

ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि विभागीय निरीक्षकों, खाद्य व औषधि निरीक्षकों की यात्रा मार्गो पर तैनाती सुनिश्चित की जा रही है। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब्स को पूरी तरह एक्टिव मोड में लाया गया है, ताकि मौके पर ही खाद्य पदार्थों की त्वरित जांच की जा सके। उन्होंने चेकिंग टीमों को संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। जग्गी ने बताया कि पर्वतीय मार्गों में भेजे जाने वाले खाद्य पदार्थों, मिठाइयों, डेयरी उत्पादों और पेय सामग्रियों पर भी कड़ी

निगरानी रखी जा रही है। नकली दवाओं की आपूर्ति रोकने के लिए छापेमारी अभियान और अधिक तेज कर दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने दिए सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि चारधाम यात्रा, मानसखंड यात्रा और कैलाश मानसरोवर यात्रा न केवल हमारी आस्था का प्रतीक हैं, बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं। इन यात्राओं के दौरान प्रदेश में लाखों श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं, इसलिए उनका स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि यात्रा मार्गों पर कहीं भी मिलावटी खाद्य सामग्री, नकली दवाइयां या अस्वच्छ खानपान की सुविधा न मिले। पर्यटन सीजन के दृष्टिगत भी हम पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यात्रियों और आम जनता की सेहत से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा। मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब्स और निगरानी टीमें

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि राज्य में मिलावट रहित और शुद्ध खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और FDA पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। अपर आयुक्त के नेतृत्व में टीम को गढ़वाल व कुमाऊँ मंडल के दौरे पर रवाना किया गया है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर यात्रा मार्ग पर मेडिकल और खाद्य सुरक्षा सुविधाएं सक्रिय रहें। FDA द्वारा मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब्स और निगरानी टीमें लगातार सक्रिय हैं। खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, सभी जिलों में जनजागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

भगवान की आखिरी आरती कर परमधाम चली गईं

गिरजा व्यास!

डॉ. श्रीगोपाल नारसन एडवोकेट

राजस्थान के उदयपुर में रह रही गिरिजा व्यास घर मे 31 मार्च को आरती कर रही थीं, आरती करते हुए उनकी चुन्नी में नीचे रखे दीपक से आग लग गई और गिरजा व्यास 90 प्रतिशत तक जल गई।

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास का उपचार के दौरान अहमदाबाद में निधन हो गया है। गिरिजा व्यास 79 वर्ष की थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं डॉ. गिरिजा व्यास के निधन से राजस्थान समेत देशभर में शोक की लहर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनकी राष्ट्रसेवा को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने कहा कि उनका असमय जाना हम सभी के लिए एक बड़ा आघात है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता गिरिजा व्यास ने राज्य और केंद्र दोनों सरकारों में मंत्री के रूप में काम किया है। वह राजस्थान कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय महिला आयोग की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। गिरिजा व्यास ने कांग्रेस पार्टी में कई वरिष्ठ पदों पर काम किया। वहसन 1991 में उदयपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंची और नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री रहीं। उन्होंने दर्शनशास्त्र में डॉक्टरेट किया और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय एवं यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में अध्यापन कार्य किया। वे लेखिका भी रही और कवयित्री के रूप में भी नाम कमाया। उनकी आठ पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें 'एहसास के पार', 'सीप, समुन्दर और मोती' व 'नॉस्टैल्जिया' आदि शामिल है। वे सन् 1985 में राजस्थान विधान सभा से पहली बार विधायक बनीं थी व सन् 1990 तक पर्यटन मंत्री रहीं। वही वे सन्

1991 से 99 तक उदयपुर से तीन बार लोकसभा सांसद व सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री रही। उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन होने का सौभाग्य भी मिला, उसके बाद वे जून सन 2013 से मई 2014 तक केन्द्रीय कैबिनेट में शहरी आवास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री का दायित्व निभाया।

उत्तराखंड के जनकवि डॉ. अतुल शर्मा के शब्दों में, गिरिजा व्यास जब भी देहरादून आती थी, कहानीकार रेखा शर्मा व कवयित्री रंजना शर्मा को सूचित कर देती कि वे दून आ रही है और घर ज़रुर आयेगी। वे हमारे सुभाष रोड व एम के पी स्टाफ क्वाटर मे ज़रूर आती थी। घरेलू चर्चा के बाद गोष्ठी जमती थी। हमारी कविताये सुनती और अपनी ग़ज़ल सुनाती थी। उन्हे स्वाधीनता संग्राम सेनानी एवं राष्ट्रीय कवि श्रीराम शर्मा प्रेम सम्मान से भी नवाजा गया तहस। उन्होंने अपने दोने ग़ज़ल संग्रह कशिश और दासता कहते कहते और सागर सीप और मोती रेखा शर्मा को भेंट की थी।

सच कहूं तो गिरजा व्यास राजनीति में ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद भी जमीन से जुड़ी रही और स्वयं को राजनेता से पहले लेखिका या फिर कवयित्री मानती रही, यही गुण उन्हें लोकप्रिय बना गया और वे भगवान की आरती करते हुए महाप्रयाण की तरफ निकल गई। उन्हें शत् शत् नमन्।

उत्तराखंड में रेल सुविधाओं का होगा कायाकल्प

मुख्य सचिव ने ली मंडलीय रेल प्रबंधक मुरादाबाद एवं इज्जतनगर के साथ बैठक

मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में प्रदेश में संचालित विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर मुरादाबाद एवं इज्जतनगर के मंडल रेल प्रबंधक एवं शासन के उच्चाधिकारी एवं सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाईन पर विस्तार से चर्चा करते हुए प्रोजेक्ट की अद्यतन जानकारी ली।

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेललाईन का कार्य निर्धारित समय पर हो पूरा: मुख्य सचिव

मुख्य सचिव ने रेलवे एवं शासन/प्रशासन के मध्य राजस्व एवं वन भूमि आदि के मामलों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों और रेलवे के अधिकारियों से समस्याओं पर बिन्दुवार चर्चा कर मामलों को निस्तारित किया। उन्होंने जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में रेलवे, वन एवं राजस्व को संयुक्त रूप से बैठक कर भूमि अधिग्रहण एवं हस्तांतरण की प्रक्रिया का निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने परियोजना को निर्धारित समय पर पूर्ण किए जाने पर जोर दिया। कहा कि योजना की अद्यतन जानकारी समय-समय पर मुख्य सचिव कार्यालय को उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। विभिन्न टनलों के आसपास रेलवे द्वारा प्रयोग में लायी जा रही सड़कों की स्थिति काफी खराब हो चुकी है, जिसे रेलवे द्वारा दुरूस्त कराया जाना है, उन्हें बिना देरी किए तत्काल ठीक कराया जाए।

हर्रावाला रेलवे स्टेशन को पूर्ण विकसित रेलवे स्टेशन की तर्ज पर किया जाए तैयार

मुख्य सचिव ने डीआरएम श्री आर.के. सिंह से हर्रावाला रेलवे स्टेशन को एक पूर्ण विकसित रेलवे स्टेशन की तर्ज पर तैयार करने की योजना पर काम किए जाने की बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि उन्हें इसके लिए जितनी भी भूमि की आवश्यकता होगी, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। उन्होंने कहा कि योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्र के लिए डेवेलपमेंट प्लान तैयार कर लिया जाए। साथ ही, उसे रेलवे स्टेशन के प्लान के साथ शामिल करते हुए एक विस्तृत एवं एकीकृत प्लान तैयार किया जाए।

मुख्य सचिव ने शहरी विकास, पर्यटन, उद्योग और रेलवे संयुक्त रूप से भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार प्रदेशभर में रेलवे प्रोजेक्ट्स का प्लान तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 में हरिद्वार में कुम्भ मेला आयोजित होना है। उन्होंने रेलवे को इसके लिए ज्वालापुर रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण और अपग्रेडेशन की योजना तैयार कर कार्यवाही शुरू किए जाने की बात कही, ताकि कुम्भ के दौरान क्षेत्र में भीड़ प्रबन्धन और निकासी को सुव्यवस्थित ढंग से किया जा सके। उन्होंने डीआरएम मुरादाबाद एवं इज्जतनगर से, उनके सम्मुख आ रही अन्य समस्याओं की भी जानकारी ली। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार द्वारा रेलवे द्वारा कराए जा रहे कार्यों में हर सम्भव सहायता उपलब्ध करायी जाएगी एवं शासन प्रशासन स्तर से समस्याओं का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने डीआरएम इज्जतनगर श्रीमती वीना सिन्हा से टनकपुर-देहरादून कोच की आवृत्ति बढ़ाए जाने और टनकपुर-दिल्ली के बीच वंदे भारत चलाए जाने पर चर्चा की।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुन्दरम, अपर सचिव श्री विनीत कुमार एवं श्रीमती रीना जोशी सहित शासन और रेलवे के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

अपना स्वयं का मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने वाला देश का पहला जिला बना रुद्रप्रयाग

''डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क'' आपदा में भी करेगा काम

चारधाम यात्रा पर देश-विदेश से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुखद और सुगम हो इसके लिए राज्य सरकार एवं प्रशासन लगातार नए प्रयास कर रहा है। देश की सबसे कठिन पैदल यात्राओं में से एक श्री केदारनाथ धाम यात्रा ने इस दिशा में नई कीर्तिमान स्थापित किया है। केदारपुरी में दर्शन को पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को अब फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध होगी। शनिवार को इसका सफल ट्रायल होने के बाद यह सुविधा श्रद्धालुओं को समर्पित कर दी गई है। बाबा के दर्शनों को पहुंचे श्रद्धालुओं ने इसपर खुशी जाहिर करते हुए सरकार और जिला प्रशासन को इसके लिए आभार जताया है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन और जिलाधिकारी डॉ. सौरभ गहरवार की पहल पर आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील रुद्रप्रयाग जनपद ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए अपना स्वयं का मोबाइल नेटवर्क स्थापित किया है। इस नेटवर्क को ''डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क'' नाम दिया गया है।

यह नेटवर्क न केवल आपदा या किसी भी विकट परिस्थिति में लगातार संचालित रहेगा, बल्कि इसमें मोबाइल डाटा, वॉयस कॉलिंग और हाई क्वालिटी सीसीटीवी विजुअल्स की भी सुविधा उपलब्ध है।

इसी रिसोर्स नेटवर्क के तहत श्रद्धालुओं को अब फ्री वाईफाई की सुविधा मिलने जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी डॉ जीएस खाती ने बताया कि वाईफाई का फायदा उठाने के लिए वाईफाई सेटिंग पर जाकर अपना मोबाईल नंबर पंजीकृत करना होगा जिसके बाद एक ओटीपी मोबाईल नंबर पर आएगा जिसे भरने के बाद आधे घंटे तक हाय स्पीड वाईफाई का लाभ उठाया जा सकता है।

देश का पहला मॉडल

रुद्रप्रयाग देश का पहला जनपद बन गया है, जिसके पास अपना अलग और संपूर्ण मोबाइल नेटवर्क है। जुलाई 2024 में केदारनाथ पैदल मार्ग पर आई आपदा के दौरान जब अन्य मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह ठप हो गए थे, तब यही नेटवर्क यात्रियों, मजदूरों और रेस्क्यू टीमों के लिए जीवन रेखा बना। इससे रास्ते में फंसे लोगों ने अपने घरों से संपर्क किया और राहत एवं बचाव कार्यो में भी अत्यंत मदद मिली।

जानिए कैसा होगा आपका यह सप्ताह

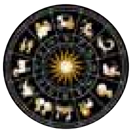
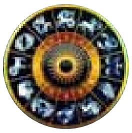
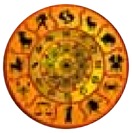

पं. दीपक प्रसाद, शास्त्री (मो. 9557730042)
(ज्योतिष, कर्मकाण्ड, धर्मिक अनुष्ठान आदि)

मेष राशि– अनुभवी लोगों से मिलने के मौके मिलेंगे। इससे आपकी सोच और दिनचर्या में अच्छा बदलाव आएगा। सामाजिक काम में आपके योगदान की सराहना होगी। कारोबार में अभी जो काम चल रहे हैं, उन्हें ठीक से करें। कोई नया काम शुरू करने की जल्दी न करें। पैसे से जुड़े मामलों में सुधार आएगा। फाइनेंस के काम सामान्य रहेंगे। प्रेम संबंधों को मजबूत बनाए रखे।

वृषभ राशि– अपनी कुशलता से मुश्किलों का सामना कर पाएंगे। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। धैर्य और संयम से अपने मन को शांत रखें। दूसरे कामों में ज्यादा व्यस्त रहने के कारण आप अपने निजी कामों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। व्यापार में नए मौके मिलेंगे, जिनसे फायदा होगा। पैसों की आवक अच्छी रहेगी।

मिथुन राशि– अध्यात्म और अपनी पसंद की चीजों में आपकी रुचि बढ़ेगी। दिनचर्या में बदलाव लाने की कोशिश सफल रहेगी। भाई-बहनों के साथ आपसी मतभेदों को शांति से और आराम से सुलझाएं। अपने आक्रामक स्वभाव और गुस्से पर काबू रखना बहुत जरूरी है। जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें। शादी के लिए अच्छा रिश्ता आने की संभावना है।

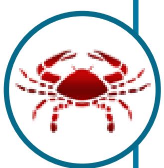

कर्क राशि– सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने से आपका संपर्क दायरा बढ़ेगा। पैसा आने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी और आप कई तरह के कामों में व्यस्त रहेंगे। पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। प्रेम संबंधों को भी परिवार की मंजूरी मिलेगी। रिश्तों में आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा। अपनी सेहत को लेकर सावधान रहें।

सिंह राशि– आपको अपने अंदर मानसिक शांति और भरपूर ऊर्जा महसूस होगी। किसी अनुभवी व्यक्ति का सही रास्ता दिखाना भी मिलेगा। व्यापार की गतिविधियां थोड़ी धीमी रहेंगी। मौजूदा हालात में धैर्य रखना ठीक है। काम करने के तरीकों में बदलाव लाएं। इस समय बाहर के नकारात्मक माहौल से अपना बचाव रखना जरूरी है। प्रेम संबंधों में भी मर्यादा बनी रहेगी।

कन्या राशि– अगर प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने की कोई योजना बन रही है, तो उसे तुरंत पूरा करें। फायदेमंद स्थितियां बनेंगी। कारोबार में मंदी का असर रहेगा। व्यवस्था में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। व्यापार को देखने का नजरिया आपकी तरक्की में सहायक रहेगा। बाहर के मौजूदा माहौल से अपना बचाव रखे। कोई इन्फेक्शन या एलर्जी होने की आशंका है।

तुला राशि– संतान की शिक्षा या भविष्य आदि से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। यह समय अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने का है, इसलिए दोस्तों के साथ या आलस में अपना समय बेकार न करें। थोड़ी सी सावधानी आपको स्वस्थ रखेगी। बाहर का खाना खाने से बचें।

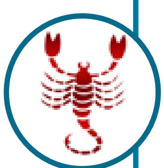

वृश्चिक राशि– विदेश जाने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए अच्छी स्थिति बनी हुई है, जल्दी ही कोई अच्छी खबर मिल सकती है। स्वभाव में गुस्सा और अहंकार के कारण घर का माहौल भी थोड़ा खराब हो सकता है। अपनी भावनाओं पर काबू रखें। परिवार के साथ मनोरंजन में बिताएं, इससे आपस में प्यार बना रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे।

धनु राशि– इस समय आप पूरे जोश में रहेंगे। आपकी बातों का असर दूसरों पर होगा। ध्यान रखें कि ज्यादा सोचने से कुछ मौके हाथ से निकल सकते हैं। विद्यार्थी लोग सोशल मीडिया और बेकार की बातों में पड़कर अपनी पढ़ाई के साथ कोई समझौता न करें। नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस के कामों में कुछ दिक्कतें रहेंगी। मेहनत जारी रखें। रिश्तों में भरोसा बनाए रखें।

मकर राशि– घर के किसी अविवाहित सदस्य के लिए शादी का अच्छा रिश्ता आ सकता है। परिवार के साथ घूमने की जगह पर जाने का प्लान बनेगा। व्यापारिक गतिविधियां अभी सामान्य ही रहेंगी। पति-पत्नी के बीच किसी गलतफहमी को लेकर तनाव रहेगा। मगर आपस में ही सुलझाने से समस्या का हल भी जरूर मिल जाएगा। अपनी ताकत से ज्यादा काम न करें।

कुंभ राशि– सामाजिक गतिविधियां बढ़ेंगी और लोगों से मिलना जुलना भी बेहतर होगा। लक्ष्य पाने का अच्छा समय है। पैसों के मामले में कुछ समस्याएं आएंगी, मगर हर मुश्किल का सामना आप निडरता से करेंगे और हल भी पा लेंगे। व्यापार के क्षेत्र में सारे फैसले खुद ही लें, किसी का दखल न होने दें। ब्लड प्रेशर, शुगर आदि की नियमित जांच करते रहें।

मीन राशि– इस समय आप जो मेहनत करेंगे, उसका आपको बहुत अच्छा नतीजा मिलेगा। यह समय खुद को समझने का भी है। फैसला लेने में इतना ज्यादा समय न लगाएं कि अच्छा मौका आपके हाथ से निकल जाए। नौकरी और बिजनेस में नए अवसर मिलेंगे। तरक्की भी हो सकती है। शादीशुदा जीवन में चल रहे मनमुटाव दूर होंगे और रिश्ते में मिठास बढ़ेगी।

अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' पहले ही दिन बनी तूफान

'रेड 2' के शुरुआती अनुमानों में लोग इसे डबल डिजिट यानी 10 करोड़ तक पहुंचने वाली फिल्म मान रहे थे। बुकिंग बढ़ी तो अनुमान लगाया गया कि फिल्म 13-15 करोड़ के बीच ओपनिंग करेगी। लेकिन फिल्म ने गुरुवार को फाइनली जिस तरह बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म किया है, 'जाट' से भी डबल ओपनिंग मिली है।

अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' के लिए रिलीज से एक दिन पहले जिस तरह एडवांस बुकिंग हो रही थी, उससे अंदाजा होने लगा था कि ये फिल्म पहले ही दिन दमदार शुरुआत करने वाली है। मगर पहले दिन अजय की फिल्म ने जिस तरह की कमाई की है उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। 'रेड 2' के शुरुआती अनुमानों में लोग इसे डबल डिजिटयानी 10 करोड़ तक पहुंचने वाली फिल्म मान रहे थे। बुकिंग की रफ्तार बढ़ी तो अनुमान लगाया गया कि फिल्म 13-15 करोड़ के बीच ओपनिंग कर सकती है। लेकिन फिल्म ने गुरुवार को फाइनली जिस तरह बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म किया है, वो हर अनुमान से कहीं ज्यादा आगे है।

रेड 2 का डायरेक्शन इसके पहले पार्ट को डायरेक्ट करने वाले राजकुमार गुप्ता ने किया है। फिल्म में अजय देवगन लीड रोल में हैं तो वहीं रितेश देशमुख नेगेटिव किरदार में दिखे हैं। वाणी कपूर, सौरभ शुक्ला और अमित स्याल भी अहम भूमिकाओं में दिखे हैं। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, रेड 2 का बजट सिर्फ 40 करोड़ है।

अजय की फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग में 2 लाख 20 हजार से ज्यादा टिकट एडवांस बुकिंग में 2 लाख 20 हजार से ज्यादा टिकट एडवांस में बुक हो चुके थे। इस दमदार बुकिंग से फिल्म ने 6.5 करोड़ रुपये से ज्यादा एडवांस ग्रॉस कलेक्शन कर लिया था। ऐसे में तय माना जा रहा था कि 'रेड 2' की नेट ओपनिंग करीब 15 करोड़ तक जा सकती है। मगर ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुमान कहते हैं कि 'रेड 2' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 18-19 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है।

'रेड 2' ने इस साल की तीसरी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनिंग दर्ज की है। इससे आगे विक्की कौशल की 'छावा' (33 करोड़) और सलमान खान की 'सिकंदर' (27.5 करोड़) हैं। 'रेड 2' की तुलना करें तो अक्षय कुमार की 'केसरी चैप्टर 2' और सनी देओल के 'जाट' की चर्चा इसके मुकाबले काफी ज्यादा नजर आ रही थी।

जहां 'केसरी 2' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 7.8 करोड़ कमाए थे, वहीं 'जाट' को पहले दिन 9.6 करोड़ की शुरुआत मिली थी। अजय की फिल्म ने पहले दिन 'जाट' से ऑलमोस्ट दोगुनी कमाई की है। जबकि 'केसरी 2' से तो इसका कलेक्शन बहुत आगे है।

लॉकडाउन के बाद अजय देवगन की बेस्ट ओपनिंग वाली फिल्म 'सिंघम अगेन' थी जिसने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 43. 70 करोड़ का कलेक्शन किया था। उनकी पिछली दो हिट्स 'शैतान' और 'दृश्यम 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ रुपये की रेंज में कलेक्शन किया था। लेकिन 'रेड 2' इन्हें पीछे छोड़ते हुए अब, लॉकडाउन के बाद अजय की दूसरी बेस्ट ओपनर बन गई है।

अजय की फिल्म को मिक्स रिव्यू मिले हैं लेकिन ऑडियंस का वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव है जो वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की रफ्तार बढ़ाएगा ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि पहले वीकेंड में 'रेड 2' कितनी कमाई करती है। दूसरे नंबर पर सिकंदर ने 26 करोड़ की ओपनिंग ली तो वहीं स्काई फोर्स तीसरे नंबर पर थी जिसने 12.25 करोड़ कमाए थे। जाट चौथे नंबर पर 9.5 करोड़ के साथ और केसरी 2 पांचवें नंबर पर 7.75 करोड़ के साथ थी।

R.N.I.: UTTHIN/2010/41629 | Postal Regd. UA/DO/DDN/01/2025-2027

Silkyara™

BADRI COW GHEE

पारंपरिक बिलौना विधि द्वारा तैयार

औषधीय गुणों से परिपूर्ण

इम्यूनिटी एवं स्मरण शक्ति बढ़ाने में लाभदायक

विटामिन्स से भरपूर

सभी प्रकार के खाना पकाने के लिए आदर्श

कुमार स्वीट्स

सहस्त्रधारा रोड पर उपलब्ध

उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र का बना दुर्लभ घी

fssai
22623030001586

UDYOG AADHAR
AADHAAR
MSME
UK050061483

Call or Whatsapp
7409782771